

सुबह की धूप

मुद्दा

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना

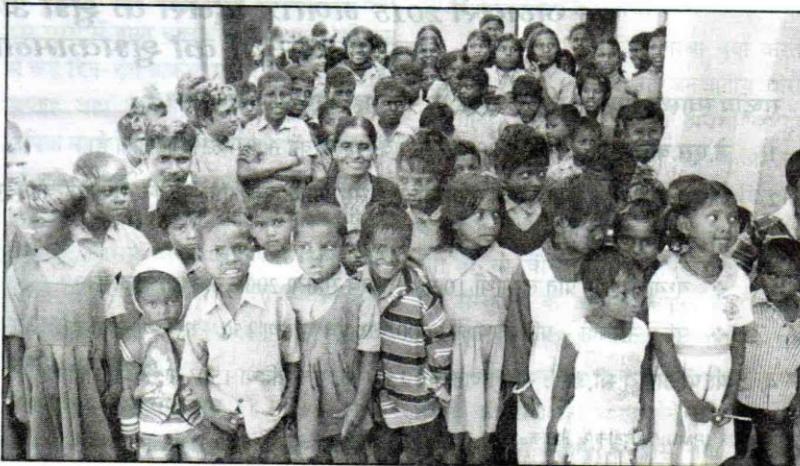


आलोका

झारखण्ड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार प्रायः नयी-नयी योजनाएं लागू करती रहती है। झारखण्ड के अस्तित्व में आने के बाद विगत 14 वर्षों में राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गयीं। कई योजनाएं बहुत सफल भी हुईं। लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसी योजनाएं आदिम जन जनजातियों को ध्यान में रख कर नहीं बनायी गयीं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के नाम पर शुरू की गयी योजनाओं में आदिम जनजातियों के लिए प्राथमिकताएं तय नहीं की गयीं। झारखण्ड गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना है। इस योजना को राज्य सरकार ने 15 नवंबर, 2011 को लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पुत्री के जन्म से समाज में फैलने वाली हीन भावना को खत्म करना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बच्चियों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, उनके विवाह में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करना शामिल था। इस योजना की घोषणा के ठीक एक वर्ष पूर्व यानी 15 नवंबर, 2010 से शुरू भी कर दी गयी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 नवंबर, 2010 के दिन से जन्मे बच्चियों को इस योजना में शामिल करते हुए

अव्यवहारिक

उन्हें लाभुक बनाना शुरू कर दिया गया। इस योजना में बालिकाओं को शामिल करने के लिए कई शर्तें / पात्रता तय की गयीं। इनमें यह नियम लागू किया गया कि बच्ची का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो और इसका प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध हो। अधिकतम दो बच्चों के बाद दंपति द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया हो। इसका भी प्रमाण-पत्र उनके पास मौजूद हो, दूसरी पुत्री को योजना का लाभ दिलाने के लिए यह जरूरी होगा कि उनके माता-पिता नसबंदी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। योजना में बच्चियों को शामिल कराने के लिए यह भी शर्त तय की गयी कि जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा। एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं होगा। प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण-पत्र संबंधित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/ नगर निकाय से निर्गत हो। ऐसी कई शर्तों को पूरा करने और लेकिन योजना की शर्तों को देखते हुए यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने वाले परिवार ही कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यह योजना योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में आदिम जनजातियों को ध्यान में रख कर नहीं शामिल होने वाली बच्चियों को मिलने वाले बनायी गयी है। आदिम जनजातियों के लिए



सुबह की धूप

मुद्रा

इस योजना की शर्तें व पात्रता पूरी करना बहद कठिन है। जंगलों में जीवन यापन करने वाले अशिक्षित आदिम जनजातियाँ जैसे बिरहोर-बैगा आदि के लिए इतने तरह के प्रमाण-पत्र जुटाना काफी मुश्किल है। इन शर्तों को पूरा करने में बिरहोर समुदाय के लिए व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। मसलन योजना में शामिल होने के लिए यह जरूरी करार दिया गया है कि बच्ची का जन्म संस्थागत प्रसव के तहत हुआ हो। यानी जिस बच्ची का जन्म किसी सरकारी या गैरसरकारी अस्पताल में हुआ हो और उसके माता-पिता के पास इसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो, तभी यह बच्ची इस योजना में शामिल हो सकती है। लेकिन बिरहोर समाज के लिए यह व्यवहारिक ही नहीं है। इस समाज के लोग जीवन यापन अपने तरीके से करते हैं। वे आमतौर पर प्रसव के लिए अस्पतालों में जाते ही नहीं हैं। ऐसे में उनके पास संस्थागत प्रसव का प्रमाण-पत्र कहां से उपलब्ध होगा। इसी तरह शर्तों में यह शामिल है कि बच्ची का जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा। साथ ही योजना के लिए आवेदन जन्म के एक वर्ष के अंदर देना होगा। एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं होगा। बिरहोर या किसी भी आदिम जनजाति के लिए ये प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराना आसान नहीं है। हालांकि आदिम जनजाति और लक्ष्मी लाडली योजना में अंतर्विरोध को सरकार ने

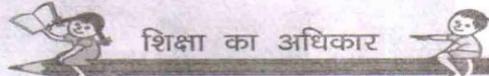


भी पहचाना है। ऐसे अंतर्विरोध को सरकार ने दूर करने का प्रयास भी किया। फिर भी बिरहोर व अन्य आदिम जन जातियों के लिए यह काफी साबित नहीं हुआ। लक्ष्मी लाडली योजना के लागू होने के कई माह बाद राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि इस योजना का उद्देश्य परिवार नियोजन को सशक्त बनाना भी है। लेकिन यह उद्देश्य आदिम जनजातियों के मामले में उल्टा पड़ गया है। क्योंकि आदिम जन जातियों का संरक्षण व संवर्द्धन पहली शर्त है। ऐसे में उनके लिए परिवार नियोजन की शर्त उचित नहीं है। फिर सरकार ने 17 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में जन्मी प्रथम या द्वितीय प्रसव से उत्पन्न बालिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत सुयोग लाभुक घोषित किया गया है, बशर्ते कि प्रसव संस्थागत हो। द्वितीय बालिका के लिए इस

□

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रामगढ़

राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर, गोला रोड, रामगढ़ केंट



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

26 जनवरी 2015 मण्टप दिवस के शुभ-अवसर पर
रामगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

जिला शिक्षा अधीक्षक
-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
रामगढ़।

पत्रांक-SSA-R/15-16/47, दिनांक-23.01.15